संपादकीय

आपराधिक लापरवाही

एक ही महीने में नकली ज़हरीली शराब की तीसरी घटना ने 120 से ज्यादा लोगों की ज़िंदगी छीन ली। यह दर्दनाक कांड असम के जोरहाट और गोलाघाट जिलों के पांच क्षेत्रों के करीब 40 कि.मी. इलाके की गरीब बस्तियों में कहर बरपा गया। इस त्रासदी का शिकार बने लगभग 400 लोग अस्पतालों में मौत से जूझ रहे हैं। इसी महीने के दूसरे सप्ताह में उ.प्र. के सहारनपुर और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 120 से ज्यादा मजदूर-पेशा हमेशा की नींद सो गए। पिछले 50 साल में पहली बार एक ही महीने में नकली शराब पीने से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं। विश्व में हमारा खुशहाली सूचकांक गिर रहा है तो दूसरी ओर हम शराब की खपत के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। इतनी तेजी से कि 2005 से 2016 के बीच यह खपत दोगुनी हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक विवेचन बताता है कि आनंद-प्रमोद के व्यसन का बीमारी बन जाने का कारण व्यक्ति का मानसिक तनाव, असंतोष और हताशा होता है। हमको इसके कारणों की पड़ताल खुशहाली के विश्व सूचकांक में करनी चाहिए। दुनिया के 155 देशों में हम नीचे खिसककर 133वें पायदान पर आ गए हैं, जबकि एक साल पहले हमारी जगह 122वीं थी। यदि आम आदमी बेचैन-परेशान है तो वह राहत की तलाश में सस्ती शराब ढूंढ़ता है।

देश में, जहां राज्य सरकारें शाही खर्च पूरे करने के लिए शराब पर भारी-भरकम टैक्स लगाती हों, सस्ती शराब किसी गरीब के लिए सुविधा है। इसका फायदा मुनाफाखोर उठाते हैं। प्रशासन की मिलीभगत से वे बेफिक्र होकर जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। देश में हर साल दो से तीन हजार लोग ज़हरीली शराब पीकर हंसती-खेलती जिन्दगी से हाथ धो बैठते हैं।

इस दारुण त्रासदी से कुछ दिन पहले उ.प्र. और उत्तराखंड में हुए हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया। अकाल मृत्यु का शिकार बनने वालों के अलावा दर्जनों लोग बीमार हैं। लगातार होने वाली ऐसी दुखद घटनाएं निकम्मे प्रशासन, भ्रष्टाचार और सरकारों की जनविरोधी लूट की ओर ध्यान दिलाती हैं। अफ़सोस! हमदर्दी और दिखावटी कानूनी कार्रवाई वाले खोखले उपायों से आगे हम कभी जा ही नहीं पाते। मौत का दुष्चक्र बदस्तूर यूं ही जारी रहता है।

ऐसा ही हादसा 2015 में मुंबई के मालवणी में हुआ था, जिसमें 106 मजदूर ज़हरीली शराब पीने से मरे?थे। आज भी वहां उसी तरह सस्ती-नकली शराब अब भी बनते हुए मिल जाएगी। ऐसे हादसों के तत्काल बाद सरकारी मशीनरी छापे और तलाशी का दिखावटी अभियान चलाती है। ज्यादा कोशिश किए बिना ही वह नकली व ज़हरीली शराब बनाने वाले ठिकानों तक पहुंच जाती है और सैकड़ों-हजारों लीटर जानलेवा पेय नष्ट करने की तस्वीरें लेकर वाहवाही के लिए आ खड़ी होती हैं। अंधाधुंध गिरफ्तारियों के साथ ही ज़हर के ये सौदागर ओझल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे फिर धंधा शुरू कर देते हैं। असम में एक ही दिन में करीब 20 हजार लीटर नकली शराब पकड़ ली गई। क्या इतनी बड़ी मात्रा एक या दो दिन में ही तैयार कर ली गई?

अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी के लिए सभी प्रदेशों में अलग विभाग कार्यरत हैं। ऐसे हादसों के सामने आने पर इन विभागों से न केवल जवाब तलब किया जाना चाहिए, वरन्? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों-कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी जरूरी है।

दुनिया में शराब का सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा आयातकर्ता भारत है। हालांकि देश में बहुत बड़े पैमाने पर कारखानों में शराब का उत्पादन होता है। इनमें तैयार की जाने वाली मदिरा का 70 प्रतिशत देश में खप जाता है। फिर भी, ज्यादा सस्ता और आसान नशा मुहैया कराने के लिए ज़हरीली वस्तुओं से तैयार ऐसे पेय बेचे जाना आम बात है। ये ही जानलेवा बन जाते है। देश के आठ राज्य ऐसे हैं, जिनमें ऐसे 70 प्रतिशत हादसों से दो-चार होना पड़ता है। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं।

हाईवे विस्तार में सावधानियां

भारत सहित अनेक देशों के विकास कार्यक्रमों में नए हाईवे बनाने व पहले के हाईवे को और चौड़ा करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पर इसके जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहे हैं उसके बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध करने व इसके आधार पर जरूरी सावधानियां अपनाने की इस समय बहुत जरूरत है। विशेषकर हिमालय व अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की दृष्टि से तो यह और भी जरूरी है। साथ ही यह पूछना जरूरी है कि विकसित देशों के लिए यह तेज यातायात की व्यवस्था कितनी महंगी पड़ी, व इसका क्या नफ ा-नुकसान हुआ। विकासशील देशों को इन हाईवे से जो उम्मीदें लगी हैं, वे कितनी जायज हैं? हाल के समय में बार-बार देखा गया है कि कहीं तो गैर-जरूरी हाईवे बनाने के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए, कहीं किसानों की उपजाऊ भूमि छिन गई या मिट्टी कटने से नष्ट हो गई, कहीं सड़क ने निकासी अवरुद्ध कर बाढ़ की समस्या को बढ़ा दिया तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनाने की प्रक्रिया में भू-स्खलन का खतरा बढ़ गया। विशेषकर हिमालय क्षेत्र में कुछ ऐसे हाईवे बन रहे हैं जिनके लिए बहुत पेड़ कटने से पर्यावरण की क्षति का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की चर्चित हाईवे परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण सबक है कि प्राय- यह मूल अनुमानों से कहीं महंगी सिद्ध होती हैं। यहां की अन्तर्राज्यीय हाईवे आज चीन जैसे विकासशील देशों का माडल बन रही हैं, पर पहले इससे जुड़े कुछ आंकड़ों को देखना जरूरी है। जब वर्ष 1956 में इसे शुरू करने वाला फैडरेल एड हाईवे अधिनियम अमेरिका में पास हुआ था, तो उम्मीद थी कि 67000 किमी. की नई सड़कें 25 अरब डालर की लागत पर 12 वर्षों में बना ली जाएंगी। वास्तव में यह कार्य इस लक्ष्य से 25 वर्ष बाद वर्ष 1993 में पूरा हुआ व इस पर कई गुणा अधिक खर्च हुआ। इनके बल पर अमेरिकी शहरों का दूर-दूर तक विस्तार फैलाने में मदद मिली, जिसने कारों पर अमेरिकी परिवारों की निर्भरता बढ़ाई जिससे तेल की खपत, प्रदूषण व ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन बहुत बढ़े। यदि इस आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति के बारे में पहले से पता होता तो अनेक हाईवे की स्वीकृति न हो पाती। आज चीन की यातायात तेज करने वाली परियोजनाएं भी बहुत महंगी हैं। बीजिंग-शंघाई हाई स्पीड लाईन की अनुमानित लागत इस समय 30 अरब डालर है। शंघाई के बीच में से गुजरने वाली एक अन्य तेज (मगलेव) रेल लाईन का बहुत विरोध यहां के नगरवासी इस आधार पर करते रहे कि इस अति तेज रफ्तार की रेल लाईन का उपयोग मात्र कुछ पर्यटक ही करेंगे, जबकि इससे नागरिकों के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जहां यातायात तेज करने के नाम पर अरबों डालर के हाईवे बनाए जा रहे हैं, वहां सड़क-शुल्क वसूल करने के लिए जो टोल-बूथ बनाए जाते हैं उनसे यातायात की रफ्तार कम भी होती है। इस शुल्क का भार बहुत बढ़ जाता है तो ट्रक व लारी ओवरलोड करने लगते हैं व इससे दुर्घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं।

भारत भी बड़े हाईवे, एक्सप्रेस वे आदि के निर्माण के दौर से गुजर रहा है। कई हाईवे को बहुत जरूरत न होने पर भी किसी व्यापक योजना के अन्तर्गत चौड़ा किया जा रहा हे। इस कारण कोई मजबूरी न होने पर भी लाखों पेड़ों को काट दिया गया है। झांसी-कानपुर हाईवे (उत्तर प्रदेश) या कोटा-बारां हाइवे (राजस्थान) जैसे कई हाईवे पर हाल के वर्षों में इस लेखक ने हजारों पेड़ों को निर्ममता से कटा हुआ पाया, जबकि इसके काटने का अभी कोई औचित्य नहीं था। बहुत से स्थानों पर हाईवे को जितना चौड़ा करना आवश्यक था, उससे अधिक विस्तार के कारण अनेक गुमटी, खोके, खोमचे, छोटी दुकान वालों के रोजगार नष्ट हो गये व उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया या उनकी गुमटी-दुकान तोड़ दिए गए। किन्तु बहुत दूर-दूर तक जाने वाले और कई लेन की चौड़ाई को समेटने वाले हाईवे से सबसे अधिक खतरा किसानों व उनके खेतों को है। चीन में जहां किसानों का भू-स्वामित्व पक्का नहीं है, वहां तथाकथित सामूहिक खेती की आड़ लेकर स्थानीय अधिकारी हाईवे परियोजनाओ आदि के लिए खेती-किसानी की भूमि हड़पने के चक्कर में है।

आतंक के आका अभी जिंदा हैं

ध्यान रहे कि इससे पहले वर्ष 2016 में उड़ी पर आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सेना ने पेराट्रुपर्स भेज कर पाक कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों और लांचिंग पैडों को तबाह कर दिया था। पाक की नापाक हरकतों के जवाब में करनी पड़ीं इन दोनों सैन्य कार्रवाइयों में एक समानता यह है कि इन्हें इतनी बेहतर योजना के साथ अंजाम दिया गया कि किसी भारतीय जवान तो दूर, ऑपरेशन में शामिल विमान तक को खरोंच नहीं आयी।

भारत ने आखिरकार पुलवामा का बदला भी ले लिया। पुलवामा में 14 फरवरी को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गये थे, जबकि लगभग इतने ही गंभीर रूप से घायल हो गये। 11 दिन बाद 26 फरवरी को तड़के साढ़े तीन-चार बजे के बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान स्थित जैश के आतंकी ठिकानों पर लगभग 1000 किलोग्राम बम गिरा कर न सिर्फ आतंकी प्रशिक्षण शिविरों और ढांचे को तबाह कर दिया, बल्कि 200-300 के आसपास आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। मारे गये आतंकियों में जैश सरगना मसूद अजहर के साले युसूफ अजहर समेत कई आतंकी प्रशिक्षक भी शामिल हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले वर्ष 2016 में उड़ी पर आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सेना ने पेराट्रुपर्स भेज कर पाक कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों और लांचिंग पैडों को तबाह कर दिया था। पाक की नापाक हरकतों के जवाब में करनी पड़ीं इन दोनों सैन्य कार्रवाइयों में एक समानता यह है कि इन्हें इतनी बेहतर योजना के साथ अंजाम दिया गया कि किसी भारतीय जवान तो दूर, ऑपरेशन में शामिल विमान तक को खरोंच नहीं आयी।

उधर, भारत की इन दोनों सैन्य कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में गजब का विरोधाभास है। उड़ी पर आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किये गये सर्जिकल स्ट्राइक के खुलासे का पाकिस्तान ने जोरदार खंडन किया था, जबकि पुलवामा पर आतंकी हमले के जवाब में मंगलवार को तड़के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के बालाकोट समेत मुजफ्फराबाद में भारतीय वायुसेना द्वारा की गयी कार्रवाई पर शोर मचाने की शुरुआत खुद पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर की। बेशक यह ट्वीट अर्धसत्य से भी परे भ्रम फैलाने वाला प्रलाप ज्यादा था। इसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर मुजफ्फराबाद में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन पाक वायुसेना की जवाबी सक्रियता के चलते उसे लौट जाना पड़ा। पाकिस्तान की दोनों प्रतिक्रियाओं में विरोधाभास को शायद आने वाले दिनों में समझ पाना आसान हो, लेकिन एक बात आईने की तरह साफ हो गयी है कि भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा करने में ही नहीं, आतंक का खूनी खेल खेलने वाले पाकपरस्त संगठनों के नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देने में भी पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि फिर ऐसी स्थितियों या आशंकाओं से भी निपटने में और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाने से भारतीय सेना को कौन रोकता रहा है, और क्यों??

ध्यान रहे कि पुलवामा पर आतंकी हमले के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेना को खुली छूट दे दी गयी है। इन दो जवाबी कार्रवाइयों से यही साबित होता है कि हमारा खुफिया तंत्र सटीक है और रक्षा तंत्र कारगर, फिर कमजोर कड़ी कौन है? पुलवामा पर हमले के बाद ही हमारी सरकार को पाक से सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा वापस लेने की सुध आयी, और पाक परस्त अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने की भी। जमीनी यथार्थ को पहचानने में इतनी देर क्यों? हम सालों से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग कर रहे हैं, पर खुद उसको हाल तक सर्वाधिक तरजीही देश बनाये रहे। क्यों? पाक के हाथों का खिलौना बने अलगाववादी नेताओं को भारतीय करदाता की मेहनत की कमाई से सुरक्षा क्यों दी जाती रही? यह भी कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अक्सर बाधक बनने वाले पत्थरबाजों के विरुद्ध मुकदमे वापस क्यों लिये गये?

सवाल यह भी उठता है कि हम कब तक वार सह कर पलटवार की मानसिकता से ग्रस्त रहेंगे? मंगलवार को भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने बेहद संयत और संतुलित टिप्पणी में कहा कि जैश द्वारा और नये आतंकी हमलों की साजिश की खुफिया सूचना मिलने के बाद भारतीय वायुसेना ने उन्हें नाकाम करने के मकसद से जैश के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। यह अच्छी बात है कि हमने आतंकी हमलों की साजिश की भनक पा कर ही उसे नाकाम करने की सक्रिय पहल की, लेकिन अतीत में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अगर किया गया होता तो न उड़ी होता और न ही पुलवामा। जैसा कि खुद विदेश सचिव ने भी मंगलवार को मीडिया को ब्रीफ करते समय याद दिलाया कि वर्ष 2004 में पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता में वचन दिया था कि वह भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी सरजमीं का इस्तेमाल नहीं होने देगा। फिर भारत को नापाक पाक की नीयत पहचान कर आत्मरक्षार्थ खुद पहल करने में डेढ़ दशक क्यों लग गया? इस बीच मुंबई पर समुद्री रास्ते से दिल दहला देने वाला आतंकी हमला भी हुआ और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला भी। यह फेहरिस्त बहुत लंबी बन सकती है, जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व को कठघरे में ही खड़ा करेगी, पर फिलहाल सवाल यह भी है कि क्या भारतीय रक्षा तंत्र की ऐसी सक्रिय पहल भविष्य में भी जारी रहेगी?

यह बेहद स्वाभाविक सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण भी इसलिए है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा इतिहास ही विश्वासघात की अंतहीन दास्तान है। पाकिस्तान ने हर बार गले मिलते हुए पीठ में छुरा घोंपा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का पैगाम लेकर बस यात्रा पर लाहौर गये थे, लेकिन बदले में कारगिल युद्ध मिला। और जब कठोर माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अचानक तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए वहां पहुंच कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, तब रिटर्न गिफ्ट के रूप में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला सामने आया था। ये, और ऐसी ही अन्य घटनाएं क्या संकेत देती हैं? पुलवामा हमले के बाद जब अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आये तो संयुक्त बयान के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुलवामा पर हमला बताता है कि बातों का समय चला गया। सवाल है कि पाकिस्तान की कथनी-करनी के बीच की खाई तथा विश्वासघात के अंतहीन सिलसिले में बातों का वक्त था कब? यह सही है कि डॉ. राममनोहर लोहिया समेत अनेक लोग भारत-पाक एकता के सपने देखते रहे। आज भी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे राजनेता हैं, जिन्हें पाक प्रधानमंत्री इमरान में बात का धनी खान नजर आता है, पर ऐसी भावनाओं के बीच भी आप इतिहास और वास्तविकता की कठोर सच्चाई को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं?

आखिर भारत विभाजन से बने पाक का आधार क्या था पृथक् राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से ही क्या पाकिस्तान का एक सूत्रीय कार्यक्रम भारत में अस्थिरता, अराजकता, अलगाववाद और आतंकवाद फैलाना नहीं रहा? अस्तित्व में आते ही पाकिस्तान की पहली कारगुजारी कश्मीर में घुसपैठ के रूप में सामने नहीं आयी थी? उसके बाद क्या सबसे ज्यादा युद्ध हमें अपने इसी नापाक पड़ोसी से नहीं लड़ने पड़े? प्रत्यक्ष युद्धों में मात खाने के बाद से क्या पाकिस्तान लगातार भारत के विरुद्ध अलगाववाद और आतंकवाद के जरिये छद्म युद्ध नहीं छेड़े हुए है? पहले पंजाब और अब कश्मीर, जिसका दंश पूरे देश में ही महसूस किया जा रहा है? इसके बावजूद अगर हमारे राजनेताओं को पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की कोई भी संभावना नजर आती है तो फिर हमें भविष्य में भी अनगिनत कारगिल, मुंबई, पठानकोट, उड़ी और पुलवामा के लिए खुद को अभिशप्त मान लेना चाहिए। हमारे राजनेता कहते रहे हैं कि एक स्थिर और खुशहाल पाकिस्तान ही भारत के हित में है, जबकि व्यावहारिक और जमीनी सच्चाई यह है कि भारत के हित कमजोर पाकिस्तान के बिखराव में ही निहित है।

वैसे पूर्वी पाकिस्तान के पृथक्? बांग्लादेश बन जाने के बाद भी सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में जैसे हालात हैं, उनमें एक देश के रूप में बिखराव ही पाकिस्तान की नियति नजर आता है। बेशक यह स्थिति एक देश के रूप में पाकिस्तान की विफलता का मुंह बोलता प्रमाण भी है, लेकिन हमें उस परिणीति के इंतजार में हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहना चाहिए। जैश के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गये—इसका सही आंकड़ा शायद ही कभी पता चल पाये, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है यह तथ्य कि आतंक के प्यादे ही मारे गये हैं, सूत्रधार अभी जिंदा हैं। अब जबकि हमारे खुफिया और रक्षा तंत्र ने अपनी क्षमता फिर साबित कर दी है, हमें पाकिस्तान के प्रलाप और भभकियों से चिंतित होने की बजाय उसकी सरजमीं पर फल-फूल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम सरीखे आतंक के आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने का समयबद्ध लक्ष्य तय करना चाहिए।

परिस्थितियों के अनुरूप पहल जरूरी

मंत्रालय ने यह परामर्श बंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुये जारी किया था। सर्कुलर से पहले पिछले साल मार्च में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभागों को परामर्श दिया था कि सरकारी कामकाज में 'दलित' शब्द के उपयोग की बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों शब्द का ही प्रयोग किया जाये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले रविवार को कुम्भ में स्नान के बाद पांच सफाई कर्मियों के पैर धोकर उन्हें पोंछना और फिर शॉल उठाकर सम्मानित करने की घटना ने अनायास ही अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले शब्द 'दलित' के औचित्य को लेकर मन में उत्कंठा पैदा कर दी। मन में सहज ही सवाल उठा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित सदस्यों के संबंध में 'दलित' शब्द की बजाय अगर उनके लिए दूसरे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाये तो शायद अधिक बेहतर होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज किये जाने का जिक्र करना अनुचित नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने हालांकि सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया लेकिन मीडिया के लिए सरकार की यह सलाह बाध्यकारी नहीं है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सात अगस्त, 2018 को मीडिया के लिए एक परामर्श सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मीडिया को अनुसूचित जाति के सदस्यों का जिक्र करते समय उनके लिए 'दलित' शब्द के उपयोग से बचा जाये और सभी शासकीय कार्यों, मामलों, प्रमाणपत्र आदि में संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह परामर्श बंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुये जारी किया था। सर्कुलर से पहले पिछले साल मार्च में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभागों को परामर्श दिया था कि सरकारी कामकाज में 'दलित' शब्द के उपयोग की बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियों शब्द का ही प्रयोग किया जाये। संविधान के अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के संबंध में है और इसी के आधार पर 2016 में सामाजिक कार्यकर्ता पंकज मेश्राम ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में एक जनहित याचिका दायर कर सरकारी कामकाज और मीडिया तथा दूसरे स्थानों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों के संदर्भ में 'दलित' शब्द का उपयोग निषिद्ध करने का अनुरोध किया था। याचिका में दलील दी गयी थी कि 'दलित' शब्द का उपयोग असंवैधानिक है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भी यही राय है कि यह शब्द भेदभाव और जातिवाद को दर्शाता है। याचिका में तर्क दिया गया था कि 'दलित' शब्द के प्रयोग से संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21 और 341 का उल्लंघन होता है। याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने पहले 29 अगस्त, 2016 को केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था और फिर उनके जवाब मिलने के बाद आठ जून, 2018 को केन्द्र को मीडिया को इस बारे में परामर्श देने पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया के लिए परामर्श जारी किया।

यह मामला जब उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो वहां वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सरकार मेरी पहचान पर ही सवाल उठाते हुये इस तरह सर्कुलर कैसे जारी कर सकती है? याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह सर्कुलर मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15,19 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। एक तर्क यह भी दिया गया कि 'दलित' शब्द स्वचयनित है और इसकी अपनी राजनीतिक पहचान है और दलित शब्द देश में सदियों तक प्रचलित रही छुआछूत की परंपरा और जाति व्यवस्था से प्रभावित भारतीय समुदाय को परिभाषित करता है।

गुजरात राज्य के लिए नाबार्ड का आकलन : 2019-20 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में 1.58 लाख करोड़ की ऋण संभावना

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 27 फरवरी 2019 को नर्मदा हॉल, स्वर्णिम संकुल, गांधीनगर में राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया। विजय रूपाणी, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सेमिनार में श्री नितिनभाई पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री, जयेश रादड़िया, माननीय मंत्री, खाद्य, नागरी आपूर्ति व उपभोक्ता मामले, कुटीर उद्योग व प्रिंटिंग, ईश्वरसिंह टी पटेल, माननीय मंत्री, युवा व सांस्कृतिक गतिविधियाँ (स्वतंत्र प्रभार) और परिवहन (राज्य मंत्री), जयद्रथसिंहजी चंद्रसिंहजी परमार, माननीय राज्य मंत्री- कृषि और स्वतंत्र प्रभार- पंचायत व पर्यावरण ने भी भाग लिया। साथ ही, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों व वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने भी सेमिनार में सहभागिता की।

विजय रूपाणी, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात ने नाबार्ड द्वारा तैयार वर्ष 2019-20 के स्टेट फ़ोकस पेपर का विमोचन किया। नाबार्ड ने राज्य में वर्ष 2019-20 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में 1,57,779 करोड़ की ऋण संभावनाएँ बताई हैं। इसमें से कृषि क्षेत्र में 85994.82 करोड़, एमएसएमई में 53676.30 करोड़ और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों 18107.82 करोड़ की ऋण संभावनाएँ हैं। (19-8)

चुनावी सौगातें

आखिरकार प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से किसान सम्मान योजना के क्रियान्वयन को हरी झंडी दिखा दी। करीब एक करोड़ लघु व सीमांत किसानों में पहली किस्त के रूप में दो हजार रुपये की राशि भेजने का दावा किया गया है। हालांकि, अभी सभी राज्यों ने किसानों की सत्यापित सूची नहीं भेजी है। कुछ राज्य मसलन तेलंगाना व ?उड़ीसा ऐसे हैं, जहां पहले से ही मिलती-जुलती योजनाएं क्रियान्वित हैं, अत- किसानों को ?इसका दोहरा लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने सूची नहीं भेजी, उन्हें यह एक चुनावी उपक्रम नजर आता है। आने वाला वक्त बतायेगा कि इस योजना का लाभ किसानों को किस सीमा तक मिलेगा। विपक्षी दल इस राशि की टुकड़ों-टुकड़ों में व्याख्या करते रहे हैं, कोई महीने के हिसाब से पांच सौ तो कोई रोज के हिसाब से सत्रह रुपये बताकर योजना को सिरे से खारिज कर रहा है। बहरहाल, इस योजना का महत्व उन गरीब किसानों के लिए खास रहेगा, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाती हैं और जो कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं।

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।

फोन-26568477, 26409779.

E : alpaviram1@yahoo.com

आईसीएआई के अहमदाबाद ब्रान्च के वर्ष 2019-20 के नये पदाधिकारी नियुक्त

अहमदाबाद : आईसीएआई के डब्ल्युआईआरसी के अहमदाबाद ब्रान्च के वर्ष 2019-20 के लिए नये पदाधिकारीगण निर्वाचित किये गये है।

सीए गणेश नादार– वाइस चेयरमेन
सीए फएनिल शाह– वाइस चेयरमेन
सीए हरित धारीवाल – सेक्रेटरी
सीए अंजली चौक्सी– ट्रेजरर

1962 में स्थापित अहमदाबाद ब्रान्च भारत में आईसीएआई की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ब्रान्च है, जिसमें 10,500 से अधिक मेम्बर्स एवं 35,000 से अधिक स्टूडेन्ट्स है। सीए गणेश नादार ने इस अवसर पर तमाम मेम्बर्स एवं मैनेजिंग कमेटी के सहयोगियों के प्रति अहमदाबाद ब्रान्च के चेयरमेन के तौर पर रखे विशअवास बदल आभार व्यक्त किया।

अहमदाबाद ब्रान्च के चेयरमेन सीए गणेश नादार ने इस मौके पर कहा कि आगामी वर्ष के दौरान नयी प्रेक्टीस एरियाज, अवसर, ब्रान्ड बिल्डींग, नेटवर्की एवं नोलेज शेरींग जैसे क्षेत्र में प्रोग्राम के आयोजन पर ध्यान केन्द्रीत किया जावेगा।

तदुपरांत युवा चेम्बर्स के प्रति विशेष ध्यान दिया जावेगा। जो नये उभरते प्रेक्टीस एरियाज में लक्ष्य दे सकें। ब्रान्च द्वारा विविध रेग्युलेटर्स एवं सत्ताधिशों के साथ अधिक विचार विमर्श शुरू किये जायेंगे। जिसमें आईसीएआई के राष्ट्र निर्माण हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त हो सके। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे इस व्यवसाय को नयी ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।(22-1)

रेड बुल पेपर विंग्स 2019 : गांधीनगर क्वोलिफायर में आर्श फेफर एवं कुलदीप बारोट की उड़ान

गांधीनगर : डीएआईआईसीटी, गांधीनगर ने 4 साल के बाद भारत में सबसे विशाल पेपर प्लेन स्पर्धा रेड बुल पेपर विंग्स 2019 का 5 वां एडीशन का पुनरागमन देखा था। इस स्पर्धा में कलात्मक रुप से पेपर का विमान बनानेवाले जोशीला सहभागी की संख्या 100 देखने मिली। विजेता दो श्रेणी में तय किये गये।जिसमें सबसे लंबा अन्तर, सबसे लम्बा हवाई समय का समावेश होता है है। अर्श फेफर एवं कुलदीप बारोट लम्बे अन्तराल एवं सबसे लम्बे हवाई समय की श्रेणी में जीत गये।जिनको अब एप्रिल में नेशनल फायनल में स्पर्धा करने का रौमांचक अवसर मिलेगा। सर्व नेशनल फायनल विजेता इसके बाद प्रतिकात्मक हेन्गर-7 में ऑस्ट्रिया में वर्ल्ड फायनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु आगे बढ़ेंगे। जहां वर्ल्ड चेम्पियन्स के ताज के लिए स्पर्धा होगी।

रेडबुल पेपर प्लेन विन्स वर्ल्ड चेम्पियनशीप विशअव के 61 से अधिक देशों में आयोजित होगी। जिसमें दुनियाभर के 304 से अधिक युनिवर्सिटियां एवं शिक्षा संस्थान के छात्र भाग ले रहे है।

रेड बुल पेपर विन्स दुनियाभर के विद्यार्थियों को ग्लोबल पेपर प्लेन चेम्पियनशीप एवं सबसे विशाल रेड बुल स्टूडेन्ट पार्टिसिपेटरी इवेन्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित है।(22-1)

आईएचजी द्‌वारा शहर में होलीडे इन एक्सप्रेस का शुभारंभ

अहमदाबाद : विश्व की अग्रणी होटल कंपनियों में से एक इन्टरकोन्टीनेन्टल होटल ग्रुप(आईएचजी) द्‌वारा होलीडे इन एक्सप्रेस की शहर के प्रहलादनगर में शुरू किये जाने की घोषणा की।यह होटल अहमदाबाद के बिजनेस एवं प्रख्यात पर्यटन स्थल जैसे कि एसजी रोड एवं उसके आसपास उभर रहे बिजनेस विस्तार, गांधीनगर, साबरमती आश्रम, लो गार्डन नाइट मार्केट, इस्कोन टेम्पल एवं इस्कोन मेगा मॉलके नजदीक भी है। होलीडे इन एक्सप्रेस अहमदाबाद प्रहलादनगर द्वारा 132 एस्थेटीकली डिजाइन ऐसे समकालिन रूम आईएचजी की सिग्नेचर होस्पिटलिटी कम्फर्ट एवं कार्यक्षमता के साथ उपलब्ध करायी जाती है। तमाम रूम बड़े पैमाने में सुविधाएं जैसे कि वॉल माउन्टेड फ्लेट स्क्रीन, टीवी, आरामदायक बेड एवं आईपोड टोकिंग स्टेशन क्लोक रेडियो के साथ सज्ज है। मेहमान इस होटल में गुणवत्तायुक्त ब्रेकफास्ट (रेट में शामिल) ले सकते है। बाद में अपनी दिनचर्या की शुरूआत करने के लिए ग्रेब एन्ड गो ओप्शन का उपयोग भी कर सकते है। आसान कनेक्टीविटी के लिए समूचे होटल में फ्री हाईस्पीड इन्टरनेट की सुविधा भी है।

इस अवसर पर आईएचजी, एसडब्ल्युए के रिज्योनल वाइस प्रेसिडेन्ट विवेक भल्ला के बताये अनुसार भारत में चार माह के विविध मार्केट्स में होलीडे-इन एक्सप्रेस होटल्स के सफल प्रारंभ के पश्चात हमने होली डे -इन एक्सप्रेस अहमदाबाद प्रहलादनगर में शुरू करने की घोषणा करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहे है। यह शहर तेजी से ग्लोबल बिजनेस एवं निवेश के लिए सबसे अच्छा प्रोमिसिंग डेस्टीनेशन बन रहा है। जहां बड़े प्रमाण में डोमेस्टिक एवं इन्टरनेशनल कार्पोरेट ट्रावेलर्स आकर्षित होते है। (13-5)

पर्सीस्टन्ट सिस्टम्स स्मार्ट इन्डिया हेक्टाथोन 2019- का आयोजन

अहमदाबाद : नॉन स्टोप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पर्धा की सबसे बड़ी आवृति तीसरी बार वापस लौटी है। एमएचआरडी, एआईसीटीई, एमआईसी, रामभआउ म्हाल्गी प्रबोधीनी एवं आई4सी के संयुक्त प्रयास से पर्सीस्टन्ट सिस्टम स्मार्ट इन्डिया हेक्टाथओन 2019 का आयोजन कर रहा है।36 घंटे का सॉफ्टवेयर ओडीशन फिनाले को भारत सरकार के एचआरडी मंत्री प्रकाश जावेडकर एवं स्मार्ट इन्डिया हेक्टाथोन 2019 के चीफ पेट्रोल द्‌वारा 2 मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जावेगा।

पर्सीस्टन्ट सिस्टम्स के चेयरमेन एवं एमडी तथा स्मार्ट इन्डिया हेक्टाथओन 2019 के को- चेयरमेन डॉ. आनंद देशपांडे ने कहा कि पर्सीस्टन्ट सिस्टम में उदभवित आईडीया को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ज राष्ट्रीय स्तर के एक डिजीटल मुहिम बन गयी है। एमएचआरडी एवं एआईसीटीई के निरंतर समर्थन एवं प्रोत्साहन के कारण, स्मार्ट इन्डिया हेक्टाथोन अनेक मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके तृतीय वर्ष में निजी क्षेत्र भी भाग ले रहे है जो दिल को छु जाते है। वास्तव में स्टूडेन्ट्स इसका लाभ उठा सकें ऐसे अनेक मौके है, जिसमें सही मायनो में राष्ट्र निर्माण के लिए संबंधित सुझाव कार्य कर सकते है। -

उपराष्ट्रपति ने इंडिया फाउंडेशन के कौटिल्य फेलो कार्यक्रम को संबोधित किया

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू कहा है कि भारत अपनी शक्ति के साथ शांति और समृद्धि चाहता है और प्रायोजित विघटनकारी मंसूबों का उचित जवाब दिया जाएगा, जैसा कि कल की वायु सेना की सफल कार्रवाई में दिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना की कार्रवाई स्वभाविक रूप से प्रतिरोधी थी और देश में शांति और समृद्धि की रक्षा में थी।

वेंकैया नायडू इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित कौटिल्य फेलोशीप कार्यक्रम में शामिल 32 देशों के लगभग 80 राजनयिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद तथा पॉलिसी थींक टैंक के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर इंडिया फाउंडेशन के निदेशक राम माधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' का दर्शन ने नजदीक और दूर के देशों के साथ विदेशी संबंधों को आकार दिया है।

नायडू ने आतंकी शिविरों पर वायु सेना की कार्रवाई के बारे में कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है लेकिन अहिंसक और शांति प्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि हम कमजोर तथा अपनी सुरक्षा और एकता पर आनेवाले खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्रगति की राह में बाधा डालने वाली विघटनकारी प्रकृतियों और शक्तियों के बारे में पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी शक्तियों को परास्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और हमें अनेक देशों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और बढ़ती बेदिमागी हिंसा के प्रति मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते।

पूरे विश्व की शांति और विकास के लिए दुनिया भर में फैले आतंकवाद की चुनौती की चर्चा करते हुए नायडू ने विश्व समुदाय से जागने और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में शामिल होने तथा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र में 1996 से लंबित है। उन्होंने ने कहा कि वैश्विक संघर्ष और युद्ध से मानव प्रगति बाधित हुई है। नायडू ने आतंकवाद के वित्त पोषण के साधनों को बंद करने के उपाय करने को कहा।

आतंकवाद की सहायता, समर्थन और धन पोषण करने और आतंकवाद को देश की नीति के रूप में अपनाने के लिए पड़ोसी देश के बारे में उन्होंने कहा कि यह देश को खोखला करने वाला है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत हर जगह शांति चाहता है और शांति प्रगति के लिए पूर्व शर्त है।

उन्होंने कौटिल्य के बारे में, जिनके नाम पर फेलोशीप कार्यक्रम रखा गया है, कहा कि कौटिल्य दूरदर्शी थे, जिन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन संचालन की व्यापक पुस्तक दी और यह पुस्तक शक्तिशाली कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक आधार है।

नायडू ने अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया और सरकार द्वारा जनधन और मुद्रा जैसी लॉच की गई योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों और सौर गठबंधन पर भारत की पहल की भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार 'प्रदान किए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार के समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने 'राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार' प्रदान किए और विजेताओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर 'खेलो इंडिया एप' भी लांच किया जो इससे संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के प्रतिभागियों एवं पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनमें छिपे हुए ओज और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव 'नए भारत' की छवि का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने युवाओं से 'नए भारत' के विजन से जुड़ने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के युवाओं को राष्ट्र एवं समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से समाज की प्रगति के लिए बेहतर संवाद कौशल विकसित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा बोले जाने वाले शब्द भले ही प्रभावशाली हों अथवा न हों, लेकिन इन्हें निश्चित तौर पर प्रेरक होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र के युवाओं से विभिन्न मुद्दों को सामने रखने और उन पर वाद-विवाद कराने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा दरअसल ओज और नए विचारों से परिपूर्ण होते हैं जिससे वे और भी ज्यादा कारगर ढंग से नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं।

प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्लेटफॉर्म युवाओं में छिपे हुए ओज को उपयुक्त दिशा एवं स्वरूप प्रदान करेगा और इसके साथ ही एक बेहतर संवाद प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे जो सांसद बनने की ख्वाहिश रखते हैं।

इससे पहले पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ अपने-अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने महोत्सव के प्रतिभागियों के साथ भी संवाद किया।

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन 'नए भारत की आवाज बनें एवं समाधान खोजें और नीति में योगदान दें' थीम पर किया गया है। इसका आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ग्रामीण इकाइयों में मूल्य वर्धन इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए वन धन योजना का विस्तार करेगा

नई दिल्ली। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम 28 फरवरी 2019 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा आयोजित कार्यशाला में 'सूक्ष्म वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं वन धन के मूल्य वर्धन संघटक' का शुभारंभ करेंगे। दिन भर चलने वाली इस कार्यशाला में 30 राज्यों की सरकारों और हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों का आमंत्रित किया गया है। इस कार्यशाला में इन प्रतिनिधियों के साथ इस योजना के प्रारंभ और उसके कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की जाएगी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अब वन धन योजना का विस्तार कर रहा है और उसे चरणबद्ध रूप से देश के सभी जनजातीय जिलों में लागू करने के लिए तैयार है। इसकी शुरूआत बड़ी जनजातीय आबादी वाले महत्वाकांक्षी जिलों के साथ की जाएगी। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वन धन योजना का शुभारंभ किया था। मंत्रालय ने सूक्ष्म वन उपज योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कवरेज के दायरे में 50 सूक्ष्म वन उत्पादों को शामिल किया है। प्रत्येक जिंस के संदर्भ में एमएसपी में 30त्न से 40त्न तक की वृद्धि की गई है।

लघु वन उपजों की खरीददारी की शुरूआत हाट बाजारों में होगी, जहां जनजातीय लोग राज्य सरकार की एजेंसियों और संबंधित जिला कलेक्टरों की सहायता के जरिए अपनी उपज लाएंगे। इसके लिए बड़ा प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। देश में प्रति 300 जनजातीय संग्रहकर्ताओं वाले लगभग 6000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस तरह लगभग 45 लाख जनजातीयों लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के रायगढ़ में दो लघु वन उपज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये इकाइयां जनजातीय संग्रहकर्ताओं और एमएसपी से लघु वन उपज प्राप्त करेंगी और उन्हें

पूरे देश में जनजातीय संस्थाओं के माध्यम से विपणन के लिए संसाधित करेंगी। इसका प्रमुख घटक पारंपरिक जनजातीय पेय हैरिटेज महुआ को मुख्यधारा में लाना होगा, जिसका उत्पादन और विपणन पूरे देश में किया जाएगा।

ट्राइफेड ने सीएसआर निधियां एकत्र करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स योजना भी प्रारंभ की है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण करने का अनुरोध किया गया है। बीपीसीएल, आईओसीएल और एसपीएमसीएल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बरवानी, राजनंदगांव, देवास और होशंगाबाद जिलों में वन धन कार्रवाइयों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

हिटाची इन्डस्ट्री एन्ड कंट्रोल ने एड्जास्टफेन वर.2019 कास्टींग सिम्युलेशन सिस्टम की बिक्री शुरू की

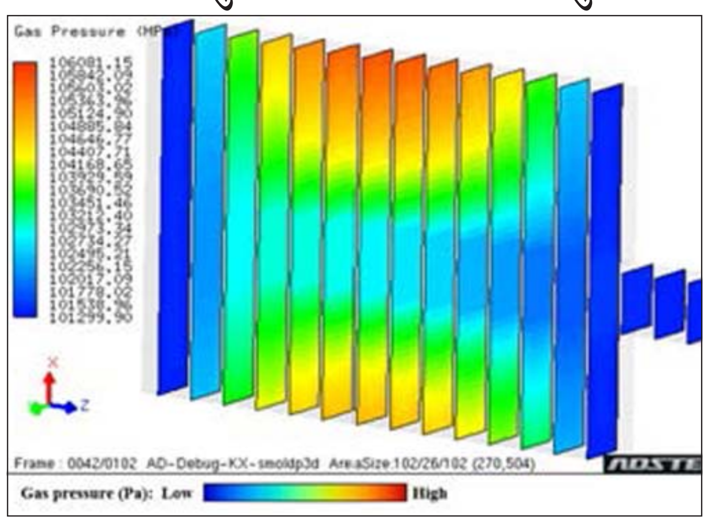

अहमदाबाद : हिटाची इन्डस्ट्री एन्ड कंट्रोल सॉल्युशन लि. द्‌वारा अपने कोस्टींग सिम्युलेशन सिस्टम एड्जास्टफेन वर. 2019 की बिक्री 1 मार्च, 2019 से जपान तथा 1 एप्रिल, 2019 से भारत, चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया में शुरू करने की घोषणा की है। एड्जास्टफेन वर. 2019 सेन्ड कास्टिंग के लिए इन मोल्ड गैस फ्लो एनालिसिस फंक्शन एवं हाल की कामगीरी में सुधार तथा विश्लेषण के लिए जरूरी समय में कमी कर सके इस तरह से नयेसिरे से सज्ज है। जो सिम्युलेशन कि जो परम्परागत पद्‌धति की अपेक्षा वास्तविकता के निकट है।

एड्सटफेन जो कास्टींग सिम्युलेशन सिस्टम है जिसमें कास्टींग क्षत्तियों का अनुमान प्राप्त कर सकते है कि जो क्षति बेज स्टोक के उत्पादन को संबंधित क्षेत्र में होते है। इस मोल्ड्स में मोल्टन मेटल्स के प्रवाह को तथा इसकी नफरत की स्थिति को सिम्युलेट करते है। इस कन्फीगरेशन के साथ, नयी सिस्टम अनेक ट्रायल मेन्युफएक्चरर्स में कमी को, डेवलपमेन्ट टर्म कमी के सहयोग एवं प्रोडक्ट क्वोलिटी में सुधार को सक्षम बनाती है। हाल में नये कन्सेप्ट के साथ प्रोडक्ट्स को विकास ऑटो मोबाइल एवं ट्रांसपोर्टेशन इन्डस्ट्रीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डस्ट्री आदि में विविधता पूर्ण आवश्यकताओं के अनुरूप की गयी है। हिटाची इन्डस्ट्री एन्ड कंट्रोल एड्जेस्टफएन की बिक्री, विस्तरण एवं निरंतर सुधार के साथ समूचे विश्व में कास्टींग इन्डस्ट्री एवं सपोर्ट इन्डस्ट्रीज के विकास में योगदान प्रदान करता है। (13-5)

मलेशिया के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ प्राइ. इन्डस्ट्रीज ने बिजनेस मीट-2019 को संबोधित किया

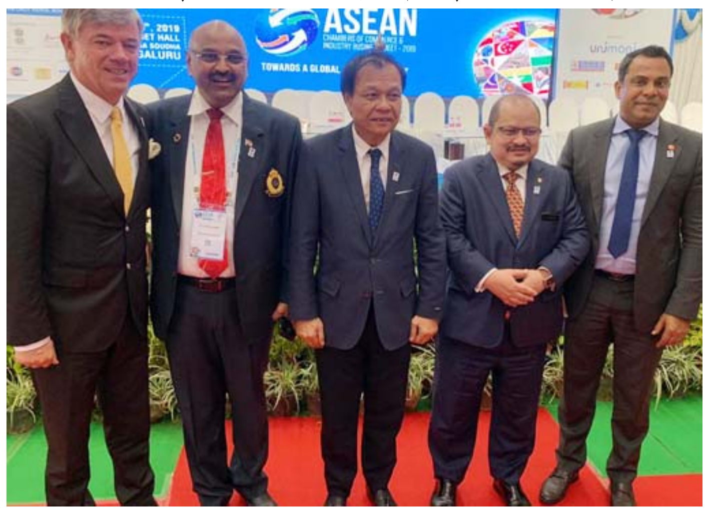

अहमदाबाद : दी फेडरेशन ऑफ कर्णाटक चेम्बर्स ऑफ कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्री द्‌वारा द ललित अशोक, बेन्गालुरू, भारत में 25 से 27 फरवरी तक एशियन चेम्बर्स ऑफ कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्री बिजनेस मीट 2019 आयोजित की। इस अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन द्‌वारा एशियन के निर्यातको एवं आयातकारो, भारत एवं दरियापार के अग्रणी कार्पोरेट्स एवं उद्‌योग के अग्रणी मैनेजमेंट, अमलदारो, नीति के गठन कारो एवं पीएसयु के प्रमुख तथा राष्ट्रीय और राज्य उद्‌योग संगठन के सदस्य एक मंच पर आये थे। इस सम्मेलन का लक्ष्य भारत एवं सहभागी देशों के लिए व्यापार, उद्‌योग एवं निवेश को प्रोत्साहित करना था। साथ ही नये गठबंधन की खओज करने लोगों के लिए उच्च स्तरिय नेटवर्कींग मंड मिले और हिस्सा धारको के सामने नयी प्रोडक्ट प्रदर्शित किये जा सके।

कार्यक्रम के शुरू होने के बाद मलेशिया के डिप्टी मिनिस्टर ओफ प्राइमरी इन्डस्ट्रीज दातुक सेरी शमसुल इस्कंदर बिन मोहम्मद अकीकन ने संबोधित किया।

मुख्य वक्तव्य से पहले उन्होंने हाल के भारत पर हुए आतंकवादी हमले पर अपनी भावनाएं व्यक्त की कि 14 फरवरी को कश्मीर के आत्मघाती बोम्बर ने भारतीय अद्‌र्धलश्करी दल के सदस्यो को लेकर जा रही बस पर विस्फोटकों से भरा वाहन टकराकर विस्फोट किया। जिसमें 40 जवानों की मृत्यु हुयी और सैकड़ों अन्य घायल हुए, वह दुखद घटना है। मैं मलेशिया का हूं, जहां इस्लाम हमारे संविधान का विधिसर धर्म है। -

महिंद्रा ने की पर्यावरणस्नेही डिजिटल अभियान की शुरुआत #RiseAgainstClimateChange के लिए जनजागृति की पहल

मुंबई, महिंद्रा ग्रुप ने आज एक नए डिजिटल कैम्पेन का शुभारम्भ करते हुए पर्यावरण की रक्षा के अपने दीर्घकालीन संकल्प की फिर एकबार पुष्टि की है। इस नए डिजिटल कैम्पेन के जरिए वृक्षारोपण का सन्देश दिया जाएगा और लोगों को #RiseAgainstClimateChange अर्थात वातावरणीय बदलावों पर उपायों में एकजुट होकर शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह फिल्म सन्देश देती है कि, इस धरती पर सबसे कड़ी मेहनत करता है पेड़, स्वयं के लिए कुछ भी पाने की उम्मीद न रखते हुए वातावरणीय बदलावों के लिए दुनियाभर के पेड़ झगड़ रहे हैं। माध्यम ही सन्देश है इस प्राचीन मान्यता को नयी ऊंचाई पर लेकर जाते हुए इस पूरी फिल्म को रद्दी कागज को रीसायकल करके बनाया गया है, इस तरह से पर्यवरण का सन्देश देनेवाली यह फिल्म अपने आप में भी पर्यावरण की रक्षा करती है, साथ ही कचरे पर पुन:प्रक्रिया का भी महत्त्व समझाती है।

महिंद्रा राइज के सभी डिजिटल चॅनेल्स पर आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है। इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर विभिन्न गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, पर्यावरण सुरक्षा में अहम् भूमिका निभानेवाले एनवायरनमेंट चैम्पियन्स का सम्मान, कुछ चुनिंदा एनजीओज के साथ मिलकर अपने अपने इलाकों में सक्रीय होने के लिए लोगों को अवसर देना आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हुए इससे पर्यावरण संवर्धन का एक आंदोलन बनता जाएगा। (1)

डीएसी ने 2700 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की आज बैठक हुई। इस बैठक में 2700 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। भारतीय नौसेना के लिए 3 कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीद की मंजूरी दी गई। इन पोतों का उपयोग महिला अधिकारियों सहित कैडेट अधिकारियों को समुद्र में प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाएगा। ये पोत अस्पताल सेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में तथा खोज व बचाव मिशन एवं आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सक्षम है।

अहमदाबाद – अजमेर एक्सप्रेस रानी स्टेशन पर रूकेगी

अहमदाबाद, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की पहल पर रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन संख्या 19411/19412 अहमदाबाद-अजमेर एक्सप्रेस को दि. 27 फरवरी 2019 से उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के रानी स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर आगामी छह माह के लिए स्टोपेज प्रदान किया जा रहा है. तदनुसार ट्रेन संख्या 19411 – अहमदाबाद- अजमेर एक्सप्रेस दि. 27 फरवरी 2019 से 14.45 बजे रानी पहुंचकर 14.46 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 19412 अजमेर-अहमदाबाद एक्सप्रेस दिनांक 27 फरवरी 2019 से प्रात: 09.14 बजे रानी स्टेशन पर पहुंचकर 09.15 बजे प्रस्थान करेगी.

स्थानीय निवासियों की मांग पर रेल मंत्रालय द्वारा उपरोक्त ठहराव 27 फरवरी 2019 से आगामी छह माह के लिये प्रदान किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं पालिताना के बीच होली विशेष एसी ट्रेन चलायेगी

अहमदाबाद, आगामी होली के अवकाश दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एवं यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस और पालिताना के बीच होली विशेष एसी ट्रेन के दो फेरे विशेष किराये के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण नीचे दिया गया है। ट्रेन सं. 09043/09044 बांद्रा टर्मिनस-पालिताना एसी विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ (2 फेरे)

ट्रेन सं. 09043 बांद्रा टर्मिनस-पालिताना एसी विशेष ट्रेन रविवार, 17 मार्च, 2019 को बांद्रा टर्मिनस से 23.55 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 15.00 बजे पालिताना पहुँचेगी।

इसी प्रकार, वापसी में ट्रेन सं. 09044 पालिताना-बांद्रा टर्मिनस एसी विशेष ट्रेन मंगलवार, 19 मार्च, 2019 को पालिताना से 13.00 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 04.45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाद, अहमदाबाद, वीरमगाम एवं बोटाद जं स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी II टियर, एसी III टियर तथा एसी चेयरकार डिब्बे होंगे।

ट्रेन सं. 09043/09044 की बुकिंग 27 फरवरी, 2019 से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रारम्भ होगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई–निविदा

टेण्डर नं. **98M/EnHM/ACWP/ERW/2018**

दिनांक : **26.02.2019**

मण्डल रेल प्रबन्धक (कैववै), उ.प.रे. बीकानेर, भारत के राष्ट्रपति महोदय एवं उनकी ओर से खुली निविदा संख्या 18/Mech/EnHM/ 2017-18 दिनांक 26.02.2019 जिसकी बंद होने की तिथि 28.03.2019 समय 15.00 बजे तक का है, के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी मैन्युअल टैण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टैण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **1. कार्य का नाम व स्थान :** कोच केयर कॉम्पलेक्स लालगढ़ में ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लॉट, ईफयूलैण्ट ट्रीटमेंट प्लॉट सहित आपूर्ति, संस्थापन व चालू करना और पाँच वर्ष तक संचालन एवं समग्र अनुरक्षण का कार्य। **2. अनुमानित लागत :** रु. 2,10,59,870/–. **3. बयाना राशि :** 2,55,300/–; ऑन लाईन नेट बैंकिंग पेमेंट और पेमेंट गेटवे के माध्यम से वरि. मण्डल वित्त प्रबन्धक, उ.प.रे. बीकानेर के पक्ष में। **4. टेंडर फार्म जमा कराने का समय व तारीख :** दिनांक 28.03.2019 समय 15.00 बजे तक। **5. निविदा खुलने की तारीख व समय :** दिनांक 28.03.2019 समय 15.30 बजे तक। **6. टेंडर फार्म शुल्क :** रु. 10000.00; ऑन लाईन नेट बैंकिंग पेमेंट और पेमेंट गेटवे के माध्यम से वरि. मण्डल वित्त प्रबन्धक, उ.प.रे. बीकानेर के पक्ष में। **7. वेबसाईट का विवरण:** www.ireps.gov.in **178-AD/19**

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे

शद्धिपत्र

वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (सवारी व माल) अजमेर भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से E-Tender Notice No. M-3-2019-All Dt. 21.02.2019 "Pest & Rodent Control in Madar based coaches and Rodent control in Pit line, yard and coaching depot premises for a period of four years." कार्य हेतु (दो पैकेट सिस्टम में) दिनांक 26.03.2019 को 15.00 बजे तक आमंत्रित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन जारी किया जाता है:– **पूर्व में प्रकाशित : कार्य की अवधि:** 60 days. **संशोधित कर पढ़ा जाय: कार्य की अवधि:** 4 years. शेष यथावत रहेगा।

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक
172-AD/19 **इंजीनियर(सवमा)/अजमेर**

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

सं.: डब्ल्यू.ए./ई-टेण्डर/11/2019 दिनांक: 25.02.2019

मण्डल रेल प्रबन्धक (निर्माण लेखा), उत्तर–पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गए कार्य के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। **1. निविदा संख्या:** 35/2019. **कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर–भीलवाड़ा उपमण्डल के कार्यक्षेत्र में विभिन्न ट्रैक सम्बन्धी कार्य करना। **अनुमानित लागत:** रुपये 85,59,373.14 **बयाना राशि:** रुपये 1,71,200/– **निविदा की अंतिम दिनांक:** 27.03.2019. **2. निविदा संख्या:** 36/2019. **कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर (लाईन) अजमेर उपमण्डल के कार्यक्षेत्र में विभिन्न ट्रैक सम्बन्धी कार्य करना। **अनुमानित लागत:** रुपये 91,56,068.78 **बयाना राशि:** रुपये 1,83,100/– **निविदा की अंतिम दिनांक:** 27.03.2019. **3. निविदा संख्या:** 37/2019. **कार्य का नाम:** अजमेर मण्डल: वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (पूर्व) के कार्यक्षेत्र में रेलवे सामग्री को परिवहन करने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 40,40,395.40. **बयाना राशि:** रुपये 80,800/–. **निविदा की अंतिम दिनांक:** 27.03.2019. **4. निविदा संख्या:** 40/2019. **कार्य का नाम:** सहायक मण्डल इंजीनियर (लाईन) अजमेर उपमण्डल के अधीन सीनियर सैक्शन इंजीनियर (कार्य) स्टेशन–अजमेर के कार्यक्षेत्र में अजमेर, आदर्शनगर, मदार माकड़वाली व पुष्कर में स्टेशनों व कॉलोनियों के मेनहोल, निरीक्षण चैम्बर्स तथा भूमिकत सीवर पाईप लाईन की सफाई व रखरखाव का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 8,61,378.02. **बयाना राशि:** रुपये 17,200/–. **निविदा की अंतिम दिनांक:** 27.03.2019. **5. निविदा संख्या:** 44/2019. **कार्य का नाम:** दौराई–ट्रैक मशीन साईडिंग का विस्तार करने तथा आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान करने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 2,18,02,626.68. **बयाना राशि:** रुपये 2,59,000/–. **निविदा की अंतिम दिनांक:** 27.03.2019. **6. निविदा संख्या:** 45/2019. **कार्य का नाम:** अजमेर–अजमेर स्टेशन पर टी.टी.ई. रेस्ट हाऊस बनाने का कार्य। **अनुमानित लागत:** रुपये 78,35,112.47. **बयाना राशि:** रुपये 1,56,700/–. **निविदा की अंतिम दिनांक:** 27.03.2019. उक्त ई–निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वैबसाईट www.ireps.gov.in पर तथा मण्डल कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, अजमेर के निविदा नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। **175-AD/19**

हमें /NWRailways पर फॉलो करें